मु.मंत्री भजनलाल ने डेढ घंटे तक बंद कमरे में भाजपा नेताओं से चर्चा की

मीटिंग को लेकर मीडिया में कयासबाजी चल रही है, किसी ने भी मीटिंग के इनपुट्स सार्वजनिक नहीं किए हैं

- झुंझुनूं में हुई इस मीटिंग में जिले के प्रभारी मंत्री अविनाश गहलोत, प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी व अन्य कई भाजपा नेता मौजूद थे।
- समझा जाता है कि, मीटिंग में झुंझुनूं विधानसभा सीट के उपचुनाव के संबंध में चर्चा की गई।

झुंझुनूं, 27 जून (निसं)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा गुरूवार को झुंझुनूं के दौरे पर रहे। मु.मंत्री ने करीब डेढ़ घंटे तक झुंझुनूं जिले के भाजपा नेताओं के साथ जिले के विकास को लेकर, संगठन की मजबूती और आने वाले उप चुनावों को लेकर चर्चा की। बैठक में जिले के प्रभारी मंत्री अविनाश गहलोत के अलावा प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी तथा संतोष अहलावत समेत अन्य कई भाजपा नेता मौजूद थे। बैठक के बाद उप चुनावों के बारे में मुख्यमंत्री ने और ना किसी ही मंत्री ने कोई चर्चा की। उन्होंने इतना जरूर कहा कि, प्रस्तावित बजट को लेकर सुझाव मांगे हैं। वहीं यमुना के पानी को लेकर प्रोग्रेस के बारे में जानकारी दी।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का दौरा मुख्यम: झुंझुनूं में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत राशि वितरण के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शामिल होने के लिए संदर्भ में था। लेकिन सियासी गलियारों में इस दौरे और कार्यक्रम को झुंझुनूं में प्रस्तावित विधानसभा उप चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। यह चर्चा उस वक्त और भी तेज हो गई जब मुख्यमंत्री ने हवाई पट्टी पर ही बंद कमरे में करीब डेढ़ घंटे तक भाजपा नेताओं के साथ बैठक की।

बैठक के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बताया कि यमुना नहर के पानी को लेकर सरकार गंभीर है। सर्वे का काम चल रहा है। वहीं जल्द ही हम जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया को शुरू करने वाले हैं। उन्होंने एक बार फिर दोहराया कि, हमने यमुना का पानी शेखावाटी तक पहुंचाने का वादा किया है।

जो हर हाल में पूरा करेंगे। उन्होंने बताया कि, आज जो बैठक उन्होंने पार्टी नेताओं के साथ की है। उसमें प्रस्तावित बजट को लेकर सुझाव मांगे हैं। झुंझुनूं जिले के विकास को लेकर भी नेताओं ने सुझाव दिए हैं। जो ना केवल झुंझुनूं जिले को, बल्कि राजस्थान को विकास की गति देंगे। उन्होंने कहा कि, सरकार हर हाल में हर वर्ग का कल्याण करने और उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए कृत संकल्पित है। उन्होंने सभी से आग्रह किया कि, वे ऑनलाइन सुझाव सरकार को भेजें। ताकि अच्छे सुझावों को बजट में शामिल किया जा सके। बैठक में भाजपा प्रदेश महामंत्री संतोष अहलावत, प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी, प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दाधीच, जिलाध्यक्ष बनवारीलाल सैनी, राष्ट्रीय परिषद सदस्य विश्वंभर पूनिया, जिला महामंत्री सरजीत चौधरी, डॉ. राजेश बाबल, विधायक विक्रम सिंह जाखल, विधायक इंजीनियर धर्मपाल गुर्जर, पूर्व विधायक शुभकरण चौधरी, पूर्व विधायक जेपी चंदेलिया, देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष ओमप्रकाश भडाना, प्यारेलाल ढूकिया आदि मौजूद थे।

जिले के प्रभारी और सूबे के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा कि, पार्टी पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों से आज मुख्यमंत्री ने चर्चा करते हुए आगामी बजट के लिए सुझाव मांगे हैं। हम चाहते है कि, झुंझुनूं की हर विधानसभा क्षेत्र की मांग पूरी हो और विकास के नए आयाम स्थापित हो सके। उन्होंने कहा कि, शौर्य उद्यान, पुलिस लाइन ओवरब्रिज, खेल यूनिवर्सिटी जैसे अधूरे प्रोजेक्ट है। उन्हें भी मुख्यमंत्री को बताया गया है। निसंदेह आने वाले दिनों में इन अधूरे प्रोजेक्टों को पूरा कराना प्राथमिकता रहेगी। अविनाश गहलोत ने भी यमुना नहर को लेकर चर्चा की और बताया कि 1994 में पहली बार तत्कालीन मुख्यमंत्री भैरोसिंह शेखावत ने ही यमुना के पानी को लेकर पत्र लिखा था। बीच के तीन दशकों में कांग्रेस का कोई नेता और कोई जनप्रतिनिधि इस मामले में नहीं बोला। लेकिन हमारी सरकार यमुना का पानी शेखावाटी में पहुंचाकर ही दम लेगी।

बैठक से बाहर आकर चाहे मुख्यमंत्री और मंत्री ने बजट के सुझावों के बारे में बात साझा की हो। लेकिन यह चर्चा भी जोरों पर है कि सीएम ने लोकसभा चुनावों में मिली हार से सबक लेने का पाठ सभी नेताओं को पढ़ाया और साफ शब्दों में कहा कि उप चुनावों में भी टिकट एक ही कार्यकर्ता को मिलेगा। लेकिन हमें एकजुटता के साथ चुनाव लड़कर झुंझुनूं की विधानसभा सीट में कमल खिलाना है। यही नहीं सीएम ने लोकसभा चुनावों में मिली हार के कारणों के बारे में भी बातचीत की। इस बारे में भी कुछ नेताओं ने अपने अपने तर्क दिए।

डिप्टी स्पीकर का पद टी.डी.पी. को मिलेगा?

नई दिल्ली, 27 जून। ओम बिरला एक बार फिर लोकसभा के स्पीकर बन गए हैं मगर डिप्टी स्पीकर का पद अभी भी खाली है। ऐसा बताया जा रहा है कि, इस बार डिप्टी स्पीकर की कुर्सी किसी विपक्षी नेता को नहीं बल्कि एन.डी.ए. अपने पास ही रख सकती है। ऐसा करके एन.डी.ए .अब तक चली आ रही परम्परा तोड़ देगी। वहीं एन.डी.ए. के इस रुख से भी सरकार और विपक्ष के बीच तकरार बढ़ने की संभावना है। ऐसा बताया जा रहा है कि, सरकार के पास भी ऐसा करने की मजबूरी है क्योंकि उसे

- चर्चा है कि, एन.डी.ए. में सामंजस्य दिखाने के मकसद से तेलुगू देशम पार्टी (टी.डी.पी.) के हरीश बालयोगी को डिप्टी स्पीकर का पद दिया जा सकता है।

अपने सहयोगी दलों को खुश करना है।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, जल्द ही एन.डी.ए. डिप्टी स्पीकर के पद पर आसीन होने वाले नाम का ऐलान कर सकती है। ऐसा बताया जा रहा है कि, सरकार के इस फैसले से विपक्ष एक बार फिर कड़ा रुख अपना सकता है। हालांकि, यह एनडीए नीत भाजपा सरकार की मजबूरी है, क्योंकि उसके लिए चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जैसे सहयोगियों को खुश रखने का सवाल भी है।

'राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान मोदी को 73 बार व राहुल को 6 बार दिखाया गया'

जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट के जरिये संसद टी.वी. की कवरेज में विपक्ष को नज़रअंदाज करने का आरोप लगाया

- राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि, राष्ट्रपति के, ''मोदी सरकार लिखित'' अभिभाषण को सुनकर ऐसा लगा कि, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 2024 के लोकसभा चुनाव के जनादेश को नकारने की कोशिश कर रहे हैं।
- खड़गे ने यह दावा भी किया कि, प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति से ''झूठ बुलवाकर'' अपनी वाहवाही करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि देश की जनता उन्हें नकार चुकी है।

नई दिल्ली, 27 जून। विपक्ष ने बृहस्पतिवार को संसद की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा दिए गए अभिभाषण के बाद केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। विपक्षी नेताओं ने अभिभाषण को ''सरकार द्वारा दी गई और झूठ पर आधारित पटकथा' करार दिया और कहा कि, सरकार को 1975 के आपातकाल के बजाय आज के ''अघोषित आपातकाल'' पर जवाब देना चाहिए। इसके अलावा, कांग्रेस ने आरोप लगाया कि, राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र को सबसे ज्यादा दिखाया गया जबकि राहुल गांधी का चेहरा बहुत कम बार दिखा।

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने गुरुवार को आरोप लगाया कि, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की तुलना में अधिक बार स्क्रीन पर दिखाया गया।

उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, ''51 मिनट के राष्ट्रपति के संबोधन में किसको कितनी बार दिखाया गया?

नेता सदन नरेंद्र मोदी : 73 बार
नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी: 6 बार
सरकार: 108 बार
विपक्ष: 18 बार

बता दें कि, राष्ट्रपति मुर्मू ने बृहस्पतिवार को अपने अभिभाषण में 1975 में लागू आपातकाल का उल्लेख किया और इसे 'संविधान पर सीधे हमले का सबसे बड़ा एवं काला अध्याय' करार देते हुए कहा कि, ऐसे अनेक हमलों के बावजूद देश ने असंवैधानिक ताकतों पर विजय प्राप्त करके दिखाई। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि, राष्ट्रपति के, ''मोदी सरकार लिखित'' अभिभाषण को सुनकर ऐसा लगा कि, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 2024 के लोकसभा चुनाव के जनादेश को नकारने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने यह दावा भी किया कि, प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति से 'झूठ बुलवाकर' अपनी वाहवाही करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि देश की जनता उन्हें नकार चुकी है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारत के दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के सरकार के दावे पर निशाना साधा। उन्होंने यहां संवाददाताओं से कहा, ''भारत के पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की कहानी बताई जा रही है... क्या उसने हमारे किसानों को समृद्ध बनाया है? अगर हम पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, तो इतने सारे युवा बेरोजगार क्यों हैं?

70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को मुफ्त इलाज मिलेगा

- राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि, सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के तहत मुफ्त इलाज योजना का दायरा बढ़ा दिया है।

नई दिल्ली, 27 जून। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संसद भवन में अपने अभिभाषण में गुरुवार को कहा कि,, आयुष्मान भारत योजना के तहत मुफ्त इलाज का लाभ अब 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को भी मिलेगा। उन्होंने संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में अपने अभिभाषण में कहा कि, देश में 25 हजार जन औषधि केंद्रों को खोलने का काम भी तेजी से चल रहा है।

राष्ट्रपति ने कहा, ''सरकार 55 करोड़ लाभार्थियों को आयुष्मान भारत योजना के तहत मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं भी उपलब्ध करवा रही है। अब इस क्षेत्र में सरकार एक और निर्णय लेने जा रही है। उनके मुताबकि, 'अब आयुष्मान भारत योजना के तहत मुफ्त इलाज का लाभ 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को भी मिलेगा।'

आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएम-जे.ए.वाय.) दुनिया की सबसे बड़ी सरकार की ओर से वित्तपोषित स्वास्थ्य बीमा योजना है। इसमें देश के 12 करोड़ निम्न आय वाले परिवारों को इलाज के लिए प्रति वर्ष प्रति परिवार पांच लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाता है।

मुर्मू ने कहा कि, भारत 'आयुष' (आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी) को बढ़ावा देकर एक स्वस्थ विश्व के निर्माण में मदद कर रहा है।

राष्ट्रपति ने कहा कि, स्वच्छ भारत अभियान ने भी गरीबों के जीवन की गरिमा से लेकर उनके स्वास्थ्य तक को राष्ट्रीय महत्व का विषय बनाया है और पहली बार देश में करोड़ों गरीबों के लिए शौचालय बनाए गए।

उन्होंने कहा, 'ये प्रयास हमें आश्वस्त करते हैं कि, देश आज महात्मा गांधी के आदर्शों का सच्चे अर्थों में अनुसरण कर रहा है।'

महिला शिक्षक ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

मानते हुए वार्षिक वेतन वृद्धि, चयनित वेतनमान और वरिष्ठता आदि का लाभ दिया गया। इसे चुनौती देते हुए याचिका में कहा गया कि, याचिकाकर्ता की नियुक्ति स्वीकृत रिक्त पद पर फरवरी में हुई थी और उसने कार्य भी ग्रहण कर लिया था। इसके अलावा विभाग ने समान प्रकृति के मामलों में दूसरे शिक्षकों को उनकी प्रथम नियुक्ति तिथि से ही सेवा परिलाभ दिए हैं। ऐसे में याचिकाकर्ता को समानता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। याचिकाकर्ता को सेवा परिलाभ देरी से देने के चलते वह वेतन, भत्ते और वरिष्ठता में अपने साथी शिक्षकों से पिछड गई। इसलिए उसे प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा परिलाभ दिए जाएं। मामले की सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिकाकर्ता को प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा परिलाभ देने को कहा है।

'राम मंदिर में पानी टपकने की रत्तीभर भी समस्या नहीं'

- श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने कहा कि, मंदिर परिसर में बिजली फिटिंग का काम चल रहा है, फिटिंग पाइप के जरिये ही पानी मंदिर की फर्श पर गिरा हुआ दिखाई दिया था।

नई दिल्ली, 26 जून (वार्ता)। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने बुधवार को कहा कि, मंदिर के गर्भगृह में पानी रिसने की रत्तीभर भी समस्या नहीं है, पर बिजली की तारों की निर्माणाधीन कंड्यूट (पाइप) के रास्ते कुछ पानी भूतल पर जरूर दिखाई दिया था, जो कोई समस्या नहीं है।

श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में छत से पिछले दिनों कथित रूप से बारिश का पानी टपकने की चर्चाओं के बीच जारी बयान में राय ने कहा, जहाँ भगवान रामलला विराजमान है, वहाँ छत से एक भी बूंद पानी नहीं टपका है और न ही कही से पानी गर्भगृह में प्रवेश हुआ है।

बयान में यह भी कहा गया है कि, मंदिर भवन में अभी निर्माण कार्य चल रहे हैं और कुछ मंडपों की छतें अभी घुम्मट आदि का निर्माण न होने से वे खुले हैं जो मानचित्र के अनुसार कार्यपूर्ण होने पर ढक जाएंगे।

राय ने बयान में कहा, चूंकि प्रथम तल पर बिजली, वाटर प्रूफिंग एवं फ्लोरिंग का कार्य प्रगति पर है अत: सभी जंक्शन बॉक्सेज़ में पानी प्रवेश करने से वही पानी कंड्यूट के सहारे भूतल पर गिरा है। उसे देखने पर यह प्रतीत हो रहा था कि, पानी छत से टपक रहा है। जबकि यथार्थ में पानी कंड्यूट पाइप के सहारे भूतल पर निकल रहा था।

बयान में कहा गया है कि, पत्थर से बने मंदिर में बिजली के कन्ड्युट (पाइप) एवं जंक्शन बाक्स का कार्य पत्थर की छत के ऊपर होता है एवं कन्ड्युट को छत में छेद करके नीचे उतारा जाता है जिससे मंदिर के भूतल के छत की लाइटिंग होती है।

आडवाणी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

की, जिसके बाद उन्हें एम्स ले जाया गया। एक सूत्र ने बताया, ''लालकृष्ण आडवानी की हालत स्थिर है। यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी और जेरिएट्रिक मेडिसिन सहित विभिन्न विशेषज्ञता वाले डॉक्टरों की एक टीम उनकी स्थिति का मूल्यांकन कर रही है।''

उल्लेखनीय है कि, केंद्र में तीसरी बार राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) की सरकार बनने के बाद भाजपा के तमाम नेता उनसे आशीर्वाद लेने पहुंचे थे। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार राजग के नेता चुने जाने के बाद आडवानी का आशीर्वाद लेने उनके आवास पर पहुंचे थे। उस समय उनका स्वास्थ्य ठीक था।

अमेरिका के ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

विफल रही है। इसका प्रतिकूल असर मुसलमानों, इसाइयों, सिख, दलितों, यहूदियों और आदिवासियों पर ज्यादा पड़ा हैं।''

उस विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा था कि यूएससीआईआरएफ को ''एक पक्षपाती संगठन के रूप में पहचाना है जिसका अपना राजनीतिक एजेन्डा है।'' प्रवक्ता ने कहा था कि यह संगठन भारत पर अपना एजेन्डा लगातार प्रकाशित करता रहता है, जो उसकी वार्षिक रिपोर्ट का एक हिस्सा हैं।'' प्रवक्ता ने यह भी आरोप लगाया था कि यह संगठन भारत के चुनावों में दखलंदाजी करने का प्रयास कर रहा हैं।''

कोटा में ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

नहीं मिला है। ऐसे में परिजनों के आने के बाद पूरे मामले की पड़ताल होगी।

हम जो वादा करते हैं उसको पूरा भी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

- कार्यक्रम में जिले के प्रभारी मंत्री और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत, सीकर की संभागीय आयुक्त, आई.जी. सत्येन्द्र सिंह कलैक्टर चिन्मयी गोपाल व अन्य प्रमुख अधिकारी मौजूद थे।

सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में राशि को 1 हजार रूपए से बढ़ाकर 1150 रूपए किया है और इसमें चरणबद्ध रूप से वृद्धि की जाएगी। संकल्प पत्र के हर एक वादे को पूरा किया जा रहा है। उन्होंने कहा '' हम पजो वादा करते हैं उसको पूरा भी करते हैं।'' उन्होंने कहा कि, 88 लाख से अधिक पैंशनरों के बैंक खातों में 1037 करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे हस्तांतरित की जा रही है। उन्होंने कहा कि, इन पैंशन योजनाओं में डिजिटल प्रक्रिया अपनाई जा रही है। जिससे आज पैंशनर्स को बिना किसी परेशानी के योजनाओं का लाभ सुनिश्चित हो रहा है। कार्यक्रम में जिले के प्रभारी मंत्री एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा कि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के सपने को साकार करने की दिशा में राज्य सरकार निरंतर काम कर रही है।

मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लाभार्थियों से संवाद भी किया। लाभार्थियों ने योजना के तहत राशि बढ़ाए जाने पर मुख्यमंत्री का बहुत-बहुत आभार व्यक्त किया। बीकानेर से मुख्यमंत्री एकल नारी पेंशन योजना की लाभार्थी कौशल्या ने मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते हुए कहा कि, पैंशन में की गई राशि बढ़ोतरी से हमें आर्थिक संबल मिला है। ब्यावर से मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना के लाभार्थी रामरत्न ने कहा कि ''पैंशन री राशि बढ़ावा वास्ते घण्णा हेत सूं.., घण्णा कोड सूं.., घण्णा मान सूं... आपरो आभार।''

जिले के प्रभारी मंत्री एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के मंत्री अविनाश गहलोत ने सभा की तैयारियों का जायजा आधी रात को लिया।

कार्यक्रम में सीकर संभागीय आयुक्त वंदना सिंघवी, आई.जी. सत्येंद्र सिंह, कलेक्टर चिन्मयी गोपाल, एस.पी राजर्षि राज वर्मा, ए.एस.पी पुष्पेंद्र सिंह राठौड़, एडीएम रामरतन सौंकरिया, सीईओ अम्बालाल मीणा, अजमेर डिस्कॉम एस.ई महेश टीबड़ा, एस.डी.एम सुमन सोनल झुंझुनूं, बृजेश कुमार चिड़ावा, नगर परिषद आयुक्त अनिता खीचड़, सी.एम.एच.ओ. डॉ. छोटेलाल गुर्जर, बी.डी.के. अस्पताल पी.एम.ओ डॉ. संदीप पचार, डी.एस.ओ. कपिल झाझड़िया, मुख्यमंत्री सुरक्षा ए.एस.पी. राजेश गुप्ता, चिड़ावा डी.एस.पी. विकास धींधवाल, सिटी झुंझुनूं डी.एस.पी वीरेंद्र शर्मा, ग्रामीण झुंझुनूं डी.एस.पी. हरिसिंह धायल, बुहाना डी.एस.पी. नोपाराम भाकर, शहर कोतवाल पवन चौबे आदि मौजूद थे।

स्पीकर ओम बिड़ला के बाद ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

संविधान ने हर चुनौती और हर परीक्षा को पास किया है।''

उन्होंने कहा, यहां तक कि संविधान निर्मित हो रहा था तब विश्व में कई ताकते थी जो भारत की विफलता की कामना कर रही थी। संवधिान के क्रियान्वयन के बाद भी इस पर कई बार हमला हुआ।''

उन्होंने कहा, ''आज 27 जून है। वर्ष 1975 में 25 जून को आपातकाल लगा था जो कि संविधान पर प्रत्यक्ष हमले का सबसे बड़ा और डरावना उदाहरण है। तब पूरा देश इस पर नाराज़ था।''

राष्ट्रपति ने कहा गत चार दशकों में हमने कश्मीर में हड़तालों व शटडाउन के बीच कम वोटर टर्न आउट देखा था। भारत के शत्रु दुनिया भर में दुष्प्रचार कर रहे थे और इसे जम्मु कश्मीर का जनमत बताते थे पर इस बार कश्मीर की जनता ने देश के भीतर और बाहर के तत्वों को माकूल जवाब दिया है। उन्होंने 2024 के चुनाव नतीजों को एन.डी.ए. सरकार के सेवा व सुशासन पर जनता की मोहर बताया।

राष्ट्रपति ने विरोधात्मक सोच आर क्षूद्र स्वार्थों की निंदा की ओर कहा कि यह प्रवृत्तियाँ लोकतंत्र की मूल भावना को कमज़ोर करती है।''

उन्होंने कहा, संसदीय व्यवस्था इससे प्रभावित होती है। साथ ही देश की विकास यात्रा पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। अस्थिर सरकारों का दौर देश के कई वर्षों तक रहा है। कई सरकारें चाह कर भी ना तो सुधार कर पाईं और ना ही महत्वपूर्ण फैसले कर पाईं। भारत की जनता ने अपने निर्णायक जनादेश से यह स्थित बदल दी है।

उन्होंने कहा कि आज पूरा विश्व लोकतंत्र के जनक का सम्मान करता है।'' भारत के लोगों ने हमेशा लोकतंत्र में पूर्ण आस्था का प्रदर्शन किया है। और चुनावी प्रक्रिया में उनका पूर्ण यकीन है। हमारे लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए हमें इस यकीन को बनाए रखना होगा। हमें समझना होगा कि लोकतांत्रिक संस्थान और चुनाव प्रक्रिया को आहत करने का अर्थ है कि जिस शाखा पर हम बैठे है उसी को काट देना हमारे लोकतंत्र की साख को कमज़ोर करने की हरेक कोशिश का हमें मिल कर विरोध करना होगा।

राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि ये ताकते देश में भी हैं और देश के बाहर से भी काम कर रही हैं ये ताकतें जनता को गुमराह करती हैं और गलत जानकारी फैलाती हैं। इस स्थिति अनियंत्रित नहीं छोड़ा जा सकता है। आज जब टैक्नॉलजी बहुत आगे बढ़ गई है। इसका दुरुपयोग मानवता के लिए घातक है। भारत ने अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी यह चिंता जाहिर की है और इसके लिए ग्लोबल फ्रेम वर्क का समर्थन किया है।'' उन्होंने कहा, यह सदी भारत की सदी है।

कर्नाटक में उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने मुख्यमंत्री बनने के जोड़-तोड़ फिर शुरु किए

मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री शिवकुमार अपना-अपना पक्ष रखने दिल्ली आए

- कर्नाटक में कांग्रेस के सत्ता संघर्ष में उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार का पलड़ा भारी लग रहा है। इसे बैलेंस करने के लिए मुख्यमंत्री सिद्धारमैया गुट के लोगों ने और ज्यादा डिप्टी सी.एम. बनाने की मांग तेज कर दी है।
- ज्ञातव्य है कि, शिवकुमार ने इसी शर्त पर सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ किया था कि, उपमुख्यमंत्री पद पर वो खुद अकेले ही काबिज रहेंगे।
- कर्नाटक कांग्रेस के सत्ता संघर्ष को उस समय और हवा मिली जब वोक्किलगा समुदाय के एक संत ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की मौजूदगी में कहा कि, वे पद से हट जाएं और डी.के. शिवकुमार को मुख्यमंत्री बनने का मौका दें।
- इसी बीच कर्नाटक भाजपा ने कांग्रेस की इस फूट का लाभ उठाने की कोशिशें शुरु कर दी हैं। भाजपा नेताओं का कहना है कि, कर्नाटक में कांग्रेस सरकार जल्द ही गिर जाएगी।

-लक्ष्मण वैंकट कुची-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 27 जून। कर्नाटक कांग्रेस में नेतृत्व की कशमकश एक बार फिर शुरु हो गई है। उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार को मुख्यमंत्री बनाने के पक्ष में पूरा माहौल बन रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री एस. सिद्धारमैया के निष्ठावान नेता भी उपमुख्यमंत्री पद लेने की फिर से मांग कर रहे हैं।

कर्नाटक कांग्रेस में, लोकसभा चुनावों के तुरन्त बाद सत्ता को लेकर आंतरिक संघर्ष पुन: शुरु हो गया है। यह कुछ ऐसा है जिसके लिए कांग्रेस हाईकमान को कुछ ना कुछ जरूर करना होगा और वह भी ऐसे समय में जबकि वह पूरे देश में पार्टी को पुर्नजीवित करने के लिए अपनी रणनीति में बदलाव की कोशिश कर रही है और खासतौर पर हिंदी भाषी प्रदेशों में उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कुछ सीटें जीतने से प्रोत्साहित होकर।

सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री, दोनों ही पार्टी हाईकमान को अपना-अपना पक्ष समझाने के लिए दिल्ली जाने वाले हैं। स्थिति यहाँ तक पहुँच गई है कि, डी.के. शिवकुमार के इस सुझाव को नामंजूर करते हुए और उपमुख्यमंत्री बनाये जाने की मांग की है और यह बात उनके शुरुआत रूख के विपरीत है। शुरु में जब उन्होंने सिद्धारमैया के पक्ष में मुख्यमंत्री ना बनना स्वीकार किया था पर उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि वे ही एक मात्र उपमुख्यमंत्री होंगे।

यह माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री के नज़दीकी मंत्री अपनी पदोन्नति की कोशिश कर रहे हैं, इसके बावजूद कि नेतृत्व में परिवर्तन की मांग शिवकुमार की तरफ से की जा रही है। वोक्कालिगा समुदाय के एक संत ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से अनुरोध किया है कि वे अपनी कुर्सी छोड़कर डी.के. शिवकुमार को राज्य का अगला मुख्यमंत्री बनने का मौका दे। एक कार्यक्रम, जिसमें मुख्यमंत्री भी उपस्थित थे, वोक्कालिगा संत चन्द्रशेखर स्वामी जी ने कहा कि हर कोई मुख्यमंत्री बनकर सत्ता सुख भोग चुका है, लेकिन हमारे डी.के. शिवकुमार अब तक मुख्यमंत्री नहीं बने हैं। उन्होंने कहा था कि सिद्धारमैया पहले भी सत्ता में रहे हैं और उन्हें शिवकुमार के लिए स्थान खाली करना चाहिए।

इस बीच भाजपा ने कांग्रेस की अटपटी स्थिति से फायदा उठाने की कोशिश की। भाजपा विधायक अश्वत्थनारायण ने कहा कि ''कांग्रेस में सत्ता संघर्ष चल रहा है। सुशासन नाम की कोई चीज़ नहीं है। भाजपा के अन्य नेता ने टिप्पणी की कि ''ऐसे वक्त में जब राज्य आवश्यक वस्तुओं में महंगाई की मार से त्रस्त है, कांग्रेस आंतरिक संघर्ष में उलझी हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री बासवराज बोम्मई सार्वजनिक रूप से कह रहे हैं कि कांग्रेस सरकार अपना कार्यकाल पूर्ण नहीं कर पाएगी और जल्दी ही गिर जाएगी।

तथापि, ना तो सिद्धारमैया और ना ही शिवकुमार ने राज्य में नेतृत्व परिवर्तन संबंधी किसी बातचीत से इन्कार किया है, लेकिन साथ ही यह भी कहा है कि ''कोई कुछ भी कह सकता है, लेकिन अंतिम निर्णय पार्टी हाईकमान को ही लेना है।'' इस बयान से यह समझा गया कि कोई आपसी समझ बन चुकी है और डी.के. शिवकुमार को ढाई साल बाद मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा, लेकिन सिद्धारमैया के नज़दीकी मंत्री पुरजोर इन्कार करते है। दिल्ली में कांग्रेस के कुछ सीनियर नेताओं ने भी इसकी पुष्टि की है।

राज्य के मंत्री एम.बी. पाटिल ने यह घोषणा कर इस मुद्दे पर विराम दिया कि सिद्धारमैया अगले पांच वर्षों तक मुख्यमंत्री रहेंगे और दोनों नेताओं के बच सत्ता शेयरिंग को लेकर कोई समझौता प्रस्ताव नहीं है। ''ए.आई.सी.सी. सचिव के.सी. वेणुगोपाल ने दिल्ली में आयोजित एक प्रैस मीट के दौरान सत्ता शेयरिंग को लेकर कुछ नहीं कहा। हालांकि उन्होंने कहा था कि सिद्धारमैया अपने पद पर बने रहेंगे और पाँच साल का अपना कार्यकाल पूर्ण करेंगे।

'क्या ओ.एम.आर. शीट ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

अधिकार तो जनता में निहित होते हैं न कि प्राइवेट संस्था में।

बैंच ने कोचिंग सैन्टर से कहा कि कोचिंग समाप्त होने के बाद उसका कोई लेना-देना नहीं रह जाता है, बैंच ने टिप्पणी में कहा ''एक कोचिंग सैन्टर की तरफ से यह याचिका आर्टिकल 32 के तहत है। आपके कौनसे मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है? उनकी मुश्किल से ही कोई इसमें भूमिका है। आपकी सेवाएं यानि कोचिंग जब खत्म हो जाती हैं तो उसके बाद आपकी जिम्मेदारी व ड्यूटी पूरी हो जाती है।

वरिष्ठ वकील बसंत ने अवकाशकालीन बैंच से कहा कि कोचिंग सैन्टर के अतिरिक्त, याचिकाकर्ता सं. 2, 3, 4 और 5 अभ्यर्थी भी हैं जो नीट-यू.जी. 2024 में उपस्थित हुए थे। कोचिंग सैन्टर की भूमिका के बारे में वरिष्ठ वकील ने कहा कि ''इन कारणों में से एक कारण कोचिंग सैन्टर का नैतिक दायित्व भी है।''

जस्टिस भट्टी ने तुरन्त कहा कि जो कोई काम केन्द्र सरकार करेगी, कोचिंग सैन्टर द्वारा भी उसका ध्यान रखा जाएगा।''

वरिष्ठ वकील बसंत ने कोर्ट से कहा कि याचिकाकर्ता विद्यार्थी (2 से 5 तक) जो कोर्ट के समक्ष हैं वो भी ओ.एम.आर. शीट्स प्राप्त करने वालों से है जो नीट-यू.जी. 2024 की परीक्षा में उपस्थित हुए थे परन्तु उन्हें अभी तक ओ.एम.आर. शीट्स उपलब्ध नहीं कराई गई है।

नीट-यू.जी. 2024 के परीक्षा परिणाम का रद्द करने की मांग को लेकर अनेक याचिकाकर्ताओं ने शीर्ष अदालत में याचिकाएं दाखिल की हैं और 5 मई को आयोजित उक्त परीक्षा का पेपर लीक होने तथा परीक्षा में अनियमितता बरतने का आरोप लगाते हुए दुबारा परीक्षा आयोजित कराने की मांग की है।

शीर्ष अदालत नीट-यू.जी. 2024 प्रवेश परीक्षा की काउन्सलिंग पर रोक लगाने की मांग को पहले ही अस्वीकार कर चुकी है जो कार्यक्रमानुसार 6 जुलाई 2024 से शुरु होने वाली है।

अठारहवीं ...

.(प्रथम पृष्ठ का शेष)

पास धरने पर बैठेंगे।

इण्डिया पार्टियों के नेता संसद भवन परिसर में, कथित राजनीतिक प्रतिशोध, विपक्ष के विरुद्ध सी.बी.आई. व ई.डी. के दुरूपयोग आदि मुद्दों को लेकर गाँधी प्रतिमा के पास धरना देंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री तथा मंत्रियों की गिरफ्तारी, हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी और पश्चिम बंगाल में तीन मंत्रियों की गिरफ्तारी को भी धरने का मुद्दा बनाया जाएगा।

मार्डन मीडिया, बीकानेर के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. 35214/79, जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033, उदयपुर कार्यालय: आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, अजमेर कार्यालय:-राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665, जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422,226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908